बकाया भुगतान को सजग हुई सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गन्ना बकाया भुगतान और वित्तीय संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को उबारने के लिए मोदी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए है। नगदी संकट से परेशान मिलों को सरकार ब्याज मुक्त अतिरिक्त कर्ज मुहैया कराने पर विचार कर रही है। विदेश से आ रही सस्ती चीनी पर रोक लगाने के लिए सरकार आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी उद्योग को कई तरह की और राहतें देने पर विचार किया जा रहा है।

नई सरकार के दिग्गज मंत्रियों की पहली बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी पत्रकारों को दी। बैठक से पहले चीनी उद्योग के नुमाइंदों ने पासवान से मुलाकात कर अपनी समस्या और उससे उबारने के तरीके पर चर्चा की थी। मंत्रियों की गुरुवार को हुई अनौपचारिक बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। चीनी निर्यात पर प्रोत्साहन सब्सिडी बढ़ाकर 3,300 रुपये टन करने और प्रत्येक दो महीने पर समीक्षा करने की जगह इसकी अवधि 2015 तक करने की मिलों की मांग पर खाद्य मंत्रालय विचार कर रहा है।

उबारने की कोशिश

- चीनी आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर 40 फीसद करने पर विचार
- मंत्रियों की बैठक में चीनी उद्योग की मांगें माने जाने के संकेत

पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा को बढ़ाने के आग्रह को भी मंत्रियों की बैठक में सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया। पासवान ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रुख सकारात्मक है। मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में गन्ने से एथनॉल बनाने पर जोर दिया गया। गन्ना खेती का रकबा बढ़ने और उत्पादन अधिक होने की वजह से बाजार में चीनी मूल्य घट जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की पूछ कम हो जाती है। लिहाजा घरेलू किसानों व चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। इसमें सुधार के लिए वैकल्पिक उपायों का सुझाव रखा गया। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल की मात्रा बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इसके लिए नियमों में संशोधन पर भी चर्चा हुई।

सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी गन्ना व उसके उत्पादों से एथनॉल बनाने के बड़े समर्थकों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर रामविलास पासवान की अध्यक्षता में दिग्गज मंत्रियों की हुई बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री सीता रमन, कलराज मिश्र, मेनका गांधी और संजीव बालियान ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नगदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों ने भुगतान से हाथ खड़े कर दिए हैं।

दैनिक जागरण
6-6-14